(b) if so, what suggestions and observations were made at the meeting; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir, the Centre for policy Research organised a seminar on 4th January, 1996 on Comprehensive Test Ban Treaty negotiations and India's policy in this regard. Participants included a number of prominent scholars, former Ministers, retired service officers and civil servants. Some senior Government officials participated in their private capacity as observers.

(b) The seminar endorsed the Government's position as articulated in Prime Minister's speeches in Kuala Lumpur and NAM summit at Cartegna that India favours a truly comprehensive treaty that is an integral part of a phased, time-bound plan of total nuclear disarmament.

(c) Government have taken note of the views expressed by the participants.

Increase in the cost of passports

581. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for frequent increase in the cost of passports;

(b) the break-up of costs and increase thereof;

(c) whether Government would streamline the system of passport issuance in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in this matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) After a period of 15 years, in July 1993, passport fee was revised from Rs. 50/to Rs. 300/for issue of a fresh passport keeping in view the increased cost of production and preparation of improved passport booklets; introduction of news procedures involving specialised equipment; and computerisation.

(c) and (d). In all passport offices, Government have and shall continue to take steps for expenditious issue of passports such as augmentation of staff strength, upgradation of office facilities including computerisation; review of systems and procedures in order to reduce delays; and regular inspections of passport offices and follow-up action.

चकमा शरणार्थियों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

582. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चकमा शरणार्थियों की समस्या के समाधान हेतु सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न उप-समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति को निश्चित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो वह समयावधि क्या थी और क्या सरकार को वह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए गए हैं और यदि सरकार को अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) से (ङ): अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं तथा हाजोंगों के मुद्दे की समग्र पृष्ठ-भूमि की जांच के लिए तथा किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, यह जानने के लिए 29 दिसम्बर, 1995 को एक उच्च स्तरीय ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप की संरचना इस प्रकार है:-

(i) श्री एस.बी. चव्हाण, अध्यक्ष, गृह मंत्री।

(ii) श्री सैयद सिब्ते रजी, गृह राज्य मंत्री।

(iii) श्री एच. आर. भारद्वाज, राज्य मंत्री विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मामले।

(iv) श्री गेगांग अपांग, मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश।

(v) श्री वी.के. जैन, विशेष सचिव (आई.एस.पी.) गृह मंत्रालय।

(vi) श्री बी.एन. झा, संयुक्त सचिव (एन.ई.) गृह मंत्रालय।

(vii) श्री डी.सी. सांखला, गृह आयुक्त अरुणाचल प्रदेश सरकार।